भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2780

जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

मोबाइल हैंडसेट का विनिर्माण

2780. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विक्रय किए जाने वाले मोबाइल हैंडसेटों सहित देश में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश मोबाइल हैंडसेट अब घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं और यदि हाँ, तो घरेलू उत्पादन स्तर और विनिर्माण एवं संयोजन में महाराष्ट्र की विशिष्ट हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2025 के आकड़ों पर आधारित अध्ययन सहित हाल के अध्ययनों की जाँच की है, जिनमें यह दर्शाया गया है कि यद्यपि मोबाइल फोन संयोजन में तेजी से विस्तार हुआ है, परन्तु वास्तविक घरेलू मूल्य संवर्धन का स्तर, विशेषकर महाराष्ट्र के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरों में, अपेक्षाकृत सीमित बना हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है जिनमें बताया गया है कि मेक इन इंडिया और उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत उच्च स्थानीयकरण अपेक्षाओं के बाद भी, महाराष्ट्र स्थित संयंत्र सहित, देश में एप्पल आईफोन जैसे केवल कुछ ही उच्च-स्तरीय उपकरणों का निर्माण किया जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का महाराष्ट्र के मोबाइल हैंडसेट उद्योग में कलपुर्जों के और अधिक विनिर्माण, आपूर्ति-श्रृंखला विकास और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नए या संशोधित नीतिगत उपायों का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** भारत सरकार की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

हमने देश में तैयार उत्पादों के निर्माण और फिर मॉड्यूल विकसित करने पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा शुरू की। अब उप-मॉड्यूल/घटकों और इसके निर्माण में जाने वाले कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं।

पिछले 11 वर्षों में भारत में मोबाइल फोन उत्पादन और निर्यात में भी काफी विस्तार हुआ है। यह वृद्धि निम्नलिखित आँकड़ों में दिखाई देती है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
भारत में मोबाइल विनिर्माण इकाइयां	2 इकाइयाँ	300 इकाइयाँ	150 गुना बढ़ा
मोबाइल फोन का उत्पादन	रु. 0.18 लाख करोड़	रु. 5.5 लाख करोड़	28 गुना बढ़ा
मोबाइल फोन का निर्यात	रु. 0.01 लाख करोड़	रु. 2 लाख करोड़	127 गुना बढ़ा
आयात किए गए मोबाइल फोन (कुल इकाइयों का %)	मांग का 75%	मांग का 0.02%	

यह परिवर्तन सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रणनीति के माध्यम से हुआ है। पिछले 11 वर्षों में कई पहल की गई हैं। इसमे शामिल है:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)।
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)।
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017
- टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि सहित कराधान में सुधार किए गए हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

भारत दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा है और मोबाइल विनिर्माण में आत्मनिर्भरता तक पहुंच गया है।

इस समय, भारत में बेचे जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल हैंडसेट 'मेड इन इंडिया' हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत में बेचे जाने वाले लगभग 74% मोबाइल फोन आयातित थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित भूमि, बिजली, सामान्य सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करना है।

ईएमसी 2.0 के तहत, 297 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए 492.85 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ रंजनगांव, पुणे में एक ग्रीनफील्ड ईएमसी को मंजूरी दी गई है। ईएमसी में अनुमानित निवेश लगभग 2 हजार करोड़ रुपये है।

वर्तमान में, इस क्लस्टर में दो एंकर इकाइयां उपभोक्ता उपकरणों और इससे संबंधित घटकों का निर्माण कर रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में मूल्यवर्धन को और अधिक गहरा करने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) शुरू की।

इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, निष्क्रिय घटकों, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, उप-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर और पूंजीगत सामान जैसे घटकों के निर्माण का समर्थन करना है।

इस योजना में घटक आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम को विकसित करने और अपने कार्यकाल के दौरान 91,600 व्यक्तियों के रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई है।

इस योजना को उद्योग से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। 59,350 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के मुकाबले, उद्योग ने 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 12,704 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश और 17,003 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के साथ 24 आवेदनों को मंजूरी दी है।

इन 24 स्वीकृत आवेदनों में से 1,122 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश और 1,583 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के साथ महाराष्ट्र राज्य के लिए तीन (3) आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसका विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

सरकार ने ईसीएमएस योजना में भाग लेने के लिए उद्योग से आवेदन आमंत्रित किए थे, जो अखिल भारतीय प्रकृति की है।

राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित सहायक नीति और व्यापार करने में आसानी के अन्य उपायों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण इकाइयों का स्थान उद्योग द्वारा तय किया जाता है।

इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी धीरे-धीरे बढ़ा है। मोबाइल फोन के विभिन्न हिस्से जैसे संलग्नक, बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल आदि धीरे-धीरे भारत में विभिन्न मोबाइल कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थानीयकृत हो रहे हैं।

****

अनुबंध I

महाराष्ट्र राज्य के लिए स्वीकृत आवेदनों की सूची

क्र. सं.	**आवेदक का नाम**	**उत्पाद**
1	सिर्मा मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली
2	यूनो मिंडा लिमिटेड	कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली
3	टीई कनेक्टिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कनेक्टर्स

*****